देश की सभी पंचायतों में पैक्स के होने से मजबूत होगा कोऑपरेटिव आंदोलन

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार जागरण

वर्ष : 03 – अंक : 01 – अप्रैल 2025

आजादी के सात दशक बाद देश को मिला पहला

सहकारी विश्वविद्यालय

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से प्रति वर्ष आठ लाख लोग होंगे प्रशिक्षित

छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किला नई पीढ़ी को स्वधर्म व स्वराज के लिए प्रेरित करता रहेगा

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ

सर्व सहकार सर्व साकार
सहकार जागरण
अप्रैल 2025, अंक 01, वर्ष 03

संपादक मंडल

प्रधान संपादक
डॉ. सुधीर महाजन
संपादक
संजय कुमार वर्मा
सहायक संपादक
डॉ श्रीजा सिन्हा

सहकार जागरण से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें:
sahakarjagran@gmail.com
ncui.pub@gmail.com

प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।
निदेशक (प्रकाशन/जनसंपर्क),
एनसीयूआई
एनसीयूआई कैंपस, 3, अगस्त क्रांति मार्ग, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली: 110016

सहकार जागरण से जुड़ने के अन्य पते:

Ministry of Cooperation

NCUI हाट

CEAS-LMS

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 'सहकार जागरण' पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाता है, और इस पत्रिका के प्रकाशन के किसी भी हिस्से की सामग्री की प्रतिलिपि, पुनः उत्पादन या पुनर्वितरण संपादक पैनल और सामग्री के लेखक/लेखकों जैसा भी लागू हो, उनकी लिखित सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन या पार्टी नहीं कर सकती है। पत्रिका में प्रदर्शित सामग्री तथा आंकड़ें प्राथमिक और अनुषंगी स्रोतों (उद्योग विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार आदि) से लिए गए हैं। पत्रिका में उपलब्ध आंकड़ों और रिपोर्टों के स्रोतों के संबंध में, न तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और न ही इसके कर्मचारी किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इस संबंध में उनका कोई कानूनी दायित्व है।

05

आवरण कथा

आजादी के सात दशक बाद देश को मिला पहला सहकारी विश्वविद्यालय

वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के केंद्र सरकार के विभिन्न पहलों से इस क्षेत्र में कुशल पेशेवरों, नवाचार और नई रणनीतियों की मांग बढ़ी है।

12

देश की सभी पंचायतों में पैक्स के होने से मजबूत होगा कोऑपरेटिव आंदोलन

मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव मंत्रालय की स्थापना और उसके बाद से अब तक के साढ़े तीन वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने बहुत सारा काम किया है। सहकारिता के विकास के लिए सभी राज्यों को साथ लेकर सहकारिता डेटाबेस तैयार हुआ है, जिससे अब देश के सभी राज्यों, जिले और गांवों की सहकारी समितियों की जानकारी इस डेटाबेस में उपलब्ध है।

आदिवासी समाज के विकास के लिए विशेष अभियान चला रहा केंद्र — 14

शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ कर रहा अंब्रेला संगठन 'नैफकब' — 16

छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किला नई पीढ़ी को स्वधर्म व स्वराज के लिए प्रेरित करता रहेगा — 18

भारत के विकास मॉडल को स्वीकार कर रही दुनियाः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी — 20

काशी की तरह पूर्वोत्तर की पुलिसिंग का तीर्थ बनेगी नई अकादमी — 22

'कैच द रेन' अभियान के लिए एक बार फिर देश ने कस ली कमर — 24

बोडोलैंड में शांति स्थापित करने में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की महत्वपूर्ण भूमिका — 26

28

मिजोरमवासियों की तीन दशक पुरानी मांग हुई पूरी

नए युग का सूत्रपात

देश की सहकारी व्यवस्था को उन्नत बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय संसद ने 'त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल-2025' को मंजूरी दे दी है। इसके बाद जल्द ही गुजरात के आणंद में इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इससे देश में लंबे समय से सहकारी क्षेत्र में कुशल एवं पेशेवर मानव संसाधन की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और सहकारी क्षेत्र में शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाशक्ति का सहज समावेश हो सकेगा। इससे निश्चय ही भारतीय सहकारिता को सहकारी योजनाओं के अनुरूप विविध पाठ्यक्रमों में दक्ष ऐसे युवाओं को नेतृत्व का अवसर मिलेगा, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण को कार्यरूप में परिणत करने में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करेंगे। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के समग्र विकास और विस्तार के लिए विश्वस्तरीय आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था होने पर सहकारिता ग्रामीण उन्नति एवं विकास का एक सशक्त माध्यम बनेगा, जो देश के लाखों होनहार युवाओं को इससे जुड़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा।

वास्तव में जब ग्रामीण भारत की प्रतिभाओं को सहकारी शिक्षण एवं उपयुक्त प्रशिक्षण मिलेगा तो वे स्वतः ही ग्राम्य संस्कृति से जुड़ी सहकारिता की विरासत को आगे बढ़ाने को ही अपने कार्य-व्यवसाय का माध्यम बनाएंगे, जो कि निश्चित रूप से गांवों के समग्र विकास के साथ ही हमारी सामाजिक संरचना को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे प्रतिभावान लोगों को स्थानीय स्तर पर ही आजीविका उपलब्ध हो सकेगी और उन्हें पलायन कर अन्यत्र प्रवासी के रूप में जीवन यापन से मुक्ति भी मिलेगी।

वर्तमान समय में भारतीय सहकारिता डेयरी, उर्वरक रसायन व मत्स्य उत्पादन आदि क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनी हुई है। सहकारिता विश्वविद्यालय के माध्यम से भारतीय सहकारिता को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और कौशल प्रशिक्षण मिलने पर निश्चय ही देश में सहकारिता क्षेत्र को विविध कार्य क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी। इससे वैश्विक धरातल पर हमारी भूमिका बढ़ेगी और सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं को विदेशों में भी कार्य के बेहतर अवसर मिलेंगे।

दरअसल, भारतीय संविधान में सहकारिता राज्यसूची का विषय है और इसीलिए देश के सहकारी क्षेत्र की राज्य स्तरीय समितियों में नियमों-उपनियमों एवं प्रावधानों में इतनी विविधता रही है कि सहकारी क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय एवं एकरूप पाठ्यक्रम का विचार ही नहीं हो सका। सहकारी समितियों के कार्य व्यवसाय के विकास व विस्तार के लिए वर्षों से यह मांग हो रही थी कि सहकारी क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र रूप से नियामक मंत्रालय का गठन हो, जो इसकी बुनियादी आवश्यकताओं का समाधान की पहल कर सके। सहकारिता मंत्रालय के गठन से भारत के सहकारी क्षेत्र में विकास के नवयुग का सूत्रपात हुआ। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना से देश में सहकारी विकास को न केवल समुचित दिशा और गति मिलेगी बल्कि सहकारी तंत्र में सुयोग्य प्रतिभाओं को स्थान मिलने पर कार्यात्मक गुणवत्ता के प्रति जनसामान्य का विश्वास सुदृढ़ होगा।

पत्रिका के इस अंक में भारत सरकार, विशेषतः सहकारिता मंत्रालय की उपयोगी योजनाओं के साथ-साथ रोचक एवं विकासपरक जानकारियों को उपलब्ध कराया गया है। आशा है कि पूर्व की भांति सहकार जागरण का यह अंक भी आपको पसंद आएगा।

जय सहकार

बीते 10 वर्षों में हमारे प्रयासों से देश में कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। हमारे लाखों छोटे किसानों को मिल रही आर्थिक मदद से बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ी है। इसके साथ ही कृषि की लागत कम हुई है और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

अब सहकारी शिक्षा भारतीय शिक्षा व पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनेगी और त्रिभुवन विश्वविद्यालय के माध्यम से देशभर के प्रशिक्षित युवा सहकारी क्षेत्र को अधिक व्यापक, सुव्यवस्थित और आधुनिक युग के अनुकूल बनाएंगे।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से सहकारी कार्यक्षमता, पारदर्शिता, डिजिटल नवाचार, अंतरराष्ट्रीय मानकों पर संस्थान, व नई फंडिंग रणनीतियों जैसे लाभ मिलेंगे—संगठनों के सतत विकास की नई दिशा!

श्री कृष्ण पाल गूजर
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

यह हर्ष का विषय है कि देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय सहकारी नेतृत्व को नई दिशा देगा। इससे सहकारी संगठनों से जुड़े लोग आधुनिक प्रबंधन और विपणन में दक्ष बनेंगे।

श्री दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

राष्ट्रीय महत्व की त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी और सहकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति की आधारशिला सिद्ध होगी। ग्रामीण युवाओं को नेतृत्व, नवाचार और सामाजिक उद्यमिता के माध्यम से समावेशी एवं सतत विकास के मार्ग पर अग्रसर करना भी इसका उद्देश्य होगा।

सहकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

आजादी के सात दशक बाद देश को मिला पहला

सहकारी विश्वविद्यालय

सहकार जागरण टीम

- त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से सहकारिता क्षेत्र में कुशल पेशवरों की मांग पूरी करने में मिलेगी मदद
- यूनिवर्सिटी की स्थापना से सहकारिता क्षेत्र में युवा नेतृत्व और आधुनिक शिक्षा से युक्त मानव संसाधन होंगे तैयार
- अंतरराष्ट्रीय मानकों पर सहकारी संस्थाओं के निर्माण और नई योजनाओं के विकास का रास्ता होगा साफ

वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के केंद्र सरकार के विभिन्न पहलों से इस क्षेत्र में कुशल पेशेवरों, नवाचार और नई रणनीतियों की मांग बढ़ी है। इसे पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे शिक्षण संस्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो न सिर्फ सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा दे सके, बल्कि कुशल युवा प्रबंधकों को तैयार कर सहकारी संगठनों की कार्यक्षमता में सुधार को बल मिले। इसी के मद्देनजर देश में पहला केंद्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने की संकल्पना की गई, जो कि सहकारिता क्षेत्र में कुशल पेशेवरों के आने से पारदर्शिता को बढ़ावा देने, डिजिटल नवाचार के तहत सहकारी प्लेटफार्मों पर अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय मानकों पर सहकारी संस्थानों के निर्माण और नई योजनाओं के विकास के लिए वित्तीय रणनीतियों के सृजन जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को सफल बनाने में मददगार भी होगा। इसके लिए संसद के बजट सत्र के पहले चरण में दोनों सदनों में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, 2025 पेश किया गया और इसे सत्र के दूसरे चरण में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के

सहकारी शिक्षण संस्थानों के बीच सेतु बनेगा

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी में डेयरी, मत्स्य, चीनी, बैंकिंग, ग्रामीण ऋण, सहकारी वित्त, सहकारी मार्केटिंग और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को पाठ्यक्रम में खासतौर पर प्रमुखता दी जाएगी। जिन राज्यों में सहकारी संस्थाओं की अधिकता है उनमें चार से पांच कॉलेजों को सहकारी विश्वविद्लाय से संबद्ध किया जाएगा और बाकी राज्यों में एक से दो सहकारी कॉलेज इससे संबद्ध किए जाएंगे। इसे वैश्विक स्तर के सहकारी विश्वविद्यालयों और सहकारी संस्थानों से भी संबद्ध किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह देशभर में सहकारी प्रबंधन संस्थानों को जोड़ने की एक कड़ी के रूप में काम करेगा। सहकारी संस्थाओं के अलग-अलग प्रशिक्षण और प्रबंधन डिप्लोमा व डिग्री कार्यक्रमों का डिटेल तैयार कर लागू करेगा। इसमें पारंपरिक भारतीय आर्थिक दर्शन को समकालीन प्रबंधन तकनीकों के साथ एकीकृत किया जाएगा। वैदिक परंपराओं से प्रेरित होकर छात्र इसमें स्थायी कृषि पद्धतियों, नैतिक व्यावसायिक आचरण और समुदाय-संचालित आर्थिक मॉडल के बारे में सीखेंगे।

इस विश्वविद्यालय का एक अन्य उद्देश्य पूरे भारत में सहकारी शिक्षा को मानकीकृत करना है। सहकारी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय संस्थान के रूप में भी कार्य करेगा, जो आईसीएआर केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, सीएसआईआर संस्थानों, स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों और अन्य विश्वविद्यालयों से संसाधनों को एकत्रित करेगा। यह पैक्स सचिवों को प्रशिक्षित करेगा और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेगा। इससे सहकारी विकास के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। पारंपरिक एमएसपी मॉडल से आगे बढ़ाते हुए यह विश्वविद्यालय सहकारी समितियों को बाजार-संचालित समाधान और आत्मनिर्भर व्यवसाय मॉडल अपनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए सहकारी मॉडल विकसित करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे सस्ती चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

साथ ही यह कानून बन गया। गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा) के परिसर में बनने वाले इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम भारत में सहकारिता की नींव रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों में शुमार त्रिभुवन दास किशिभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। जिस गुजरात राज्य सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) को देश और दुनिया अमूल के नाम से जानती है, वह त्रिभुवन दास पटेल के विचारों की ही देन है। विश्वविद्याल के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए का शुरूआती प्रावधान किया गया है। विश्वभर में वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में, भारत में सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का यह कदम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

वास्तव में, यह सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार है। यह विश्वविद्यालय कौशल आधारित प्रशिक्षण, अनुसंधान और नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे युवाओं को सहकारी शिक्षा मिलेगी और सहकारिता क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे सहकारी क्षेत्र में समग्र शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के नए अवसर मिलेंगे। सहकारी क्षेत्र में नवीनतम शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाकर यह यूनिवर्सिटी प्रशिक्षित पेशेवरों को तैयार करेगी, जिससे देशभर में सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार आएगा। मानव संसाधन की दक्षता बढ़ने के साथ देशभर में सहकारिता के क्षेत्र में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों और संस्थागत सुधारों का सशक्त नेटवर्क स्थापित होगा।

प्रधानमंत्री का 'सहकार से समृद्धि' सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि सहकारिता मंत्रालय ने इसे जमीन पर उतारने के लिए साढ़े तीन साल में दिन-रात एक किए हैं। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से सहकारी सिद्धांतों व सहकारी गतिविधियों का विस्तार होगा और कोऑपरेटिव क्षेत्र को नई प्रौद्योगिकी का फायदा मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही अनुसंधान और नवाचार भी बढ़ेंगे, जिससे जमीनी स्तर पर कोऑपरेटिव क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

संसद द्वारा विधेयक पारित किए जाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा, 'यह विधेयक देश में सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी लाएगा। अब सहकारी शिक्षा भारतीय शिक्षा व पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनेगी और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देशभर के प्रशिक्षित युवा सहकारी क्षेत्र को अधिक व्यापक, सुव्यवस्थित और आधुनिक युग के अनुकूल बनाएंगे।'

आजादी के 75 वर्षों बाद सहकारिता क्षेत्र को समर्पित पहला सहकारी विश्वविद्यालय भारत को मिल रहा है। सरकार की इस पहल से सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारिता विश्वविद्यालय मिलेगा। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता देश में हर परिवार को छूता है। हर गांव में कोई न कोई ऐसी इकाई है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि विकास, ग्रामीण विकास और स्वरोजगार के काम में जुटी हुई है जो देश के विकास में योगदान करती है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का माध्यम बनेगा। सहकारिता को शिक्षा और कौशल से जोड़कर एक नए युग की शुरूआत करेगा।

सहकारिता क्षेत्र में गतिशीलता और अपूर्व विस्तार

राज्यसभा में बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, 'सहकारिता क्षेत्र में गतिशीलता लाने और इसके विस्तार के लिए एक संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है। इसी उद्देश्य से त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। कई सहकारी संस्थाओं में कार्य क्षमता की कमी, मैनेजमेंट में अनियमितताएं और तकनीकी संसाधनों के सीमित उपयोग जैसी चुनौतियां हैं जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र का दायरा और प्रभाव बढ़ेगा, जिससे नए स्वरोजगार और नवाचार के अवसर सृजित होंगे। पैक्स के सचिव से लेकर एपेक्स (शीर्ष) बैंक के एमडी तक, सभी स्तरों पर कार्य कुशलता और अनुशासन के लिए योग्य प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार, आगामी पांच वर्षों में सहकारिता क्षेत्र को लगभग 17 लाख प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत होगी।' फिलहाल सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और यह बिखरी हुई भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय लिया।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के मुताबिक 'एनसीसीटी और इसके इंस्टीट्यूट सालाना करीब तीन लाख लोगों को ही ट्रेनिंग दे पाते हैं। सहकारिता विश्वविद्यालय बनने से सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी कृषि के साथ ही कोऑपरेटिव को पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सिटी के आने से कोऑपरेटिव पर फोकस होकर कोर्स का निर्धारण हो सकेगा और छात्र एमफिल, पीएचडी, एमबीए आदि कर सकेंगे। एनसीसीटी और इसके 20 संस्थान भी यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे। यह यूनिवर्सिटी हब का काम करेगी और विभिन्न संस्थान उससे संबद्ध होंगे। सहकारिता बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें 30 अलग-अलग सेक्टर में काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी बनने से इन सबके लिए अलग-अलग कोर्स उपलब्ध होंगे, जिनमें शिक्षित-प्रशिक्षित होकर युवा अपना कैरियर बना सकेंगे।'

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से होने वाले लाभ

17 लाख
प्रशिक्षित युवाओं की अगले 5 साल में देश को होगी जरूरत

नवाचार और अनुसंधान में आएगी तेजी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

20 संस्थान
भी जुड़ेंगे यूनिवर्सिटी से

सहकारी क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट व Phd की पढ़ाई कर पाएंगे युवा

सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान होंगे संबद्ध

देशभर में अभी सैकड़ों की संख्या में सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान हैं, मगर किसी का कॉमन कोर्स नहीं है और न ही ये किसी एकीकृत राष्ट्रीय संस्थान से संबद्ध हैं। सहकारिता मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी बनने से पहले ही कोऑपरेटिव क्षेत्र की जरूरत को ध्यान में रख कर कोर्स डिजाइन का काम कर दिया है। यूनिवर्सिटी बनने के एक साल के भीतर देश के लगभग हर जिले में इससे जुड़े कॉलेज खोले जाएंगे या पहले से मौजूद शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को इससे संबद्ध किया जाएगा। इसके माध्यम से सहकारी सिद्धांतों और सहकारी गतिविधियों का विस्तार होगा, कोऑपरेटिव क्षेत्र को नई प्रोद्योगिकी का फायदा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

यह विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा को सुव्यवस्थित करेगा। छात्रों, सहकारी समिति के सदस्यों और उद्योग के पेशेवरों को सशक्त बनाने के लिए भी इसमें विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।■

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से प्रति वर्ष आठ लाख लोग होंगे प्रशिक्षित

सहकार जागरण टीम

> आजादी के 75 वर्षों बाद पहली बार भारत को एक समर्पित सहकारी विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ है। यह संस्थान नवाचार और शोध के माध्यम से सहकारी आंदोलन को मजबूत करेगा तथा नए नेतृत्व को प्रशिक्षित करने में अहम भूमिका निभाएगा।
>
> **श्री अमित शाह**
> **केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

देश के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के साथ ही सहकारिता क्षेत्र में कुशल व प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग को पूरा करने में सफलता मिलेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, 'त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ सहकारिता क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इस विश्वविद्यालय से प्रति वर्ष आठ लाख लोग प्रशिक्षित होंगे। इसमें शार्ट और लॉन्ग टर्म कोर्स करने वालों के अलावा चंद दिनों या हफ्ते भर तक चलने वाले ट्रेनिंग कोर्स भी शामिल होंगे। इससे पूरे देश को सहकारिता की भावना और आधुनिक शिक्षा से युक्त युवा सहकारी नेतृत्व मिलेगा। कोऑपरेटिव क्षेत्र के विकास और विस्तार को देखते हुए अगले पांच वर्ष में 17 लाख प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत है। यह यूनिवर्सिटी इस जरूरत को पूरा करने का काम करेगी। यहां से डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त युवाओं को सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं और कंपनियों में नौकरी मिलेगी।' उनके मुताबिक, इस यूनिवर्सिटी से भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भी बड़ा योगदान दे सकेगा। नये युग की सहकारी संस्कृति भी इस यूनिवर्सिटी से शुरू होगी।

वैश्विक सहकारिता में भारत की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है। सहकारी क्षेत्र परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो क्षमता और संभावनाओं से भरा हुआ है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक सहकारी समितियों में 5.5 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार और 5.6 करोड़ अतिरिक्त स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता होगी। इससे रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी सहकार से समृद्ध भारत की जो नींव

ग्रामीण प्रबंधन का उत्कृष्टता केंद्र होगा इरमा

आणंद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट (इरमा) की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। 60 एकड़ क्षेत्र में फैले इरमा को अस्तित्व में लाने में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी), स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, गुजरात सरकार और इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन का विशेष योगदान रहा है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की भूमिका अहम रही है। यहां से निकलने वाले प्रबंधकों की युवा खेप देश के विभिन्न संस्थानों को संभाल रही है। इस संस्थान की उपयोगिता को देखते हुए ही इसे सहकारिता विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय किया गया। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी अधिनियम, 2025 के प्रभावी होने के साथ ही इरमा सोसायटी भंग कर दी जाएगी। इरमा नए विश्वविद्यालय के स्कूलों में से एक बन जाएगा और इसे ग्रामीण प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया जाएगा। इसकी स्वायत्तता और पहचान विश्वविद्यालय के संस्थागत ढांचे के भीतर संरक्षित की जाएगी।

रख रहे हैं, उसमें सहकारी विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सलाहकार निकाय की भूमिका निभाएगा विश्वविद्यालय

सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से क्षेत्रीय क्षमता निर्माण, सहकारी जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और विस्तार गतिविधियों को महत्व मिलेगा। विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय सलाहकार निकाय के रूप में भी काम करेगा, सहकारी समितियों का मार्गदर्शन करेगा और सर्वोत्तम प्रथाओं, सरकारी योजनाओं और नियामक परिवर्तनों पर परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। यह विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा को नई दिशा प्रदान करेगा। यह सहकारी समितियों को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख माध्यम के रूप में स्थापित करेगा। यह वैश्विक सहकारी मॉडल, सहकारी समितियों में ब्लॉकचेन और मेंटरशिप और फंडिंग पहलों के माध्यम से सहकारी उद्यमिता को बढ़ाने की रणनीतियों पर शोध करेगा। इसका उद्देश्य ज्ञान और व्यवहार के बीच की खाई को पाटते हुए एक गतिशील संस्थान के रूप में काम करना है।

सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण को मिलेगा विस्तार

देश में राष्ट्रीय स्तर पर अभी सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग (एनसीसीटी) पर है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके नेटवर्क में 20 संस्थान हैं जो दो तरह के हैं। एक है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (आरआईसीएम), जो एक से अधिक राज्यों को देखते हैं। देश में पांच आरआईसीएम हैं। दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ कोपरेटिव मैनेजमेंट (आईसीएम), जो 14 राज्यों में है। यह मूलतः उसी राज्य में शिक्षण-प्रशिक्षण का काम देखता है जहां स्थित है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान पुणे में है जिसका नाम वैंकुठ लाल मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (वैमनीकॉम) है।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में 'सहकारिता में सहकार' का सिद्धांत जमीन पर उतारा जा रहा है। सहकारिता ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से देश के विकास के साथ भी जोड़ता है और उनके सम्मान की भी रक्षा करता है।

दूरस्थ क्षेत्रों में सहकारी शिक्षा को सुलभ बनाएगी यूनिवर्सिटी

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी सहकारी क्षेत्र के लिए योग्य और प्रशिक्षित पेशेवर प्रदान करने के लिए सहकारी शिक्षा का मानकीकरण और उन्नत करने के लिए अपने स्वयं के स्कूल और संबद्ध संस्थान स्थापित करेगा। सहकारी कर्मचारियों, बोर्ड के सदस्यों और अन्य हितधारकों के बीच क्षमता का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है। यह सहकारी शिक्षा के पूरे क्षेत्र में शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। यह दूरस्थ शिक्षा पर जोर देते हुए अंतःविषय और अत्याधुनिक तकनीक सीखने के अवसर प्रदान करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाएगा।

मोदी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) का 50 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र से उत्पन्न करने का है। अनुसंधान, प्रशिक्षण और नीतिगत पहल के माध्यम से यह मानव संसाधनों को विकसित करेगा, जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकेंगे। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को आगे बढ़ाकर और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों की ओर संचारित करके विश्वविद्यालय सहकारी समितियों को दीर्घकालिक स्थिरता के लिए तैयार करेगा। हरित प्रौद्योगिकियों, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और समावेशी शासन को प्रोत्साहित करते हुए यह पहल भारत को सतत सहकारी विकास में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगी।■

त्रिभुवनदास पटेल (1903-1994)

सहकारिता आंदोलन के पुरोधा

- ग्रामीण उत्थान, सामुदायिक स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के लिए समर्पित जीवन
- पोलसन डेयरी जैसे निजी व्यापारियों द्वारा डेयरी शोषण को समाप्त करने के लिए 14 दिसंबर 1946 को कैरा मिल्क यूनियन (अमूल) की स्थापना की

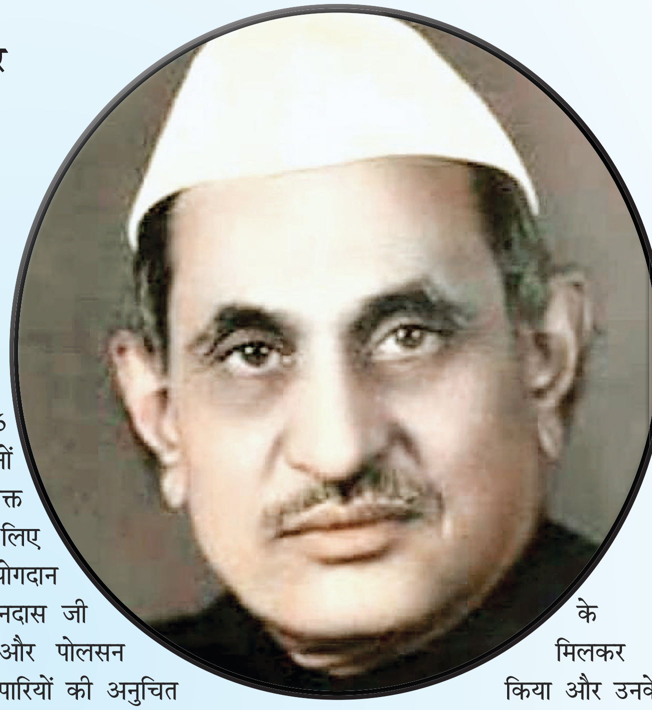

सहकार जागरण टीम

त्रिभुवनदास पटेल का जन्म 1903 में किशीभाई पटेल और लखीबा के घर गुजरात के आनंद में हुआ था। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की और वे महात्मा गांधी के दर्शन और सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे।

एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलनों, जैसे-सविनय अवज्ञा आंदोलन, ग्रामीण विकास और अस्पृश्यता व शराबखोरी आदि के खिलाफ अभियान और नमक सत्याग्रह में भाग लिया। नमक आंदोलन में भाग लेने के कारण वर्ष 1930 में नासिक में पहली बार जेल भेजे गए। उन्हें 1930 में विसापुर में दूसरी बार कैद किया गया, जहाँ से उन्होंने बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए अपना जीवन समर्पित करने की शपथ ली। वे 1948 से 1983 तक हरिजन सेवक समिति के अध्यक्ष थे।

सहकारी आंदोलन में योगदान

उन्हें भारत में 'सहकारिता आंदोलन के जनक' के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। त्रिभुवनदास जी ने डेयरी उद्योग में विशेष रूप से अनेक परिवर्तनकारी कार्य के लिए। सहकारी आंदोलन को दिशा देते हुए उन्होंने वर्ष 1946 में किसानों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। त्रिभुवनदास जी ने पोलसन और पोलसन डेयरी के व्यापारियों की अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ किसानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और 14 दिसंबर 1946 को कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना की, जिसे आज 'अमूल' के रूप में जाना जाता है। उद्देश्यों को लेकर ईमानदार और समाज सेवा के प्रति उनके प्रयासों में समर्पण ने उन्हें जनता का सम्मान दिलाया। श्री त्रिभुवनदास पटेल द्वारा अपनाया गया मूल दृष्टिकोण सबसे पहले गांवों में दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना करना था। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक गांव की सहकारी समिति गांव के सभी दूध उत्पादकों के लिए खुली होनी चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ या समुदाय के हों। उन्होंने प्रत्येक सदस्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 'एक व्यक्ति एक वोट' के सिद्धांत पर समान जोर दिया।

त्रिभुवनदास जी ने डेयरी प्लांट को आधुनिक बनाने और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर वर्गीज कुरियन के साथ मिलकर काम किया और उनके इस योगदान से भारत में श्वेत क्रांति का उदय हुआ, जिससे भारत के डेयरी सहकारी आंदोलन को विश्व स्तर पर पहचान मिली। उन्होंने सहकारी डेयरी फार्मिंग और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आणंद (आईआरएमए) की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने सहकारी समुदाय से प्राप्त धन का उपयोग सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित 'त्रिभुवनदास फाउंडेशन' की स्थापना के लिए किया। उत्कृष्ट नेतृत्व और समाज सेवा के लिए त्रिभुवनदास जी को अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें वर्ष 1963 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए फिलीपींस से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और समाज सेवा के लिए वर्ष 1964 में भारत सरकार से पद्म भूषण अलंकरण सबसे प्रमुख हैं। ■

सहकारी टैक्सी सेवा जल्द होगी शुरू

सहकार जागरण टीम

सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने के लिए देश में अब इसका दायरा बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने परिवहन क्षेत्र को चिन्हित किया है। इसके तहत देश में टैक्सी सेवा क्षेत्र को सहकारिता से जोड़ने की योजना तैयार की जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि सहकारी मॉडल पर आधारित टैक्सी सेवा जल्द ही शुरू होगी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री शाह ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की।

सहकारिता मंत्री श्री शाह ने लोकसभा में बताया कि निकट भविष्य में सहकारिता मॉडल पर एक टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। इसमें दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा और चार पहिया वाहनों का पंजीकरण हो सकेगा और लाभ सीधे समिति के सदस्य चालकों को मिलेगा। 'सहकार से समृद्धि' के सिद्धांत पर सहकारी टैक्सी सेवा के इच्छुक टैक्सी चालकों द्वारा बनाई जाएगी। इसका प्रबंधन सहकारिता टैक्सी सेवा समिति करेगी, जिससे टैक्सी संचालन से संबंधित सभी कार्य उसके सदस्यों के हाथ में ही रहेगा। इस पहल का उद्देश्य सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से लोकतांत्रिक प्रबंधन सुनिश्चित करना और ऐसी सहकारी टैक्सी सोसायटी द्वारा अर्जित लाभ को सदस्य टैक्सी चालकों के बीच समान रूप से वितरित करना है। इस तरह की पहल से समग्र समृद्धि आएगी और सहकारी समिति के सदस्य टैक्सी चालकों की आय, कार्य स्थितियों और जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें लोग स्वेच्छा से एकत्रित होकर एक सहकारी समिति बनाते हैं, जो आपसी

- **टैक्सी कोऑपरेटिव में दोपहिया, ऑटो रिक्शा और चार पहिया वाहनों का होगा पंजीकरण**
- **इच्छुक टैक्सी चालकों द्वारा बनाई जाएगी यह कोऑपरेटिव, सदस्यों के पास रहेगा प्रबंधन**
- **सहकारी टैक्सी समिति द्वारा अर्जित लाभ टैक्सी चालकों के बीच समान रूप से होगा वितरित**

लाभ और समान आर्थिक हितों पर आधारित होती है। आर्थिक सहयोग का सहकारी मॉडल सदस्यों के लिए अधिक लाभकारी, अधिक न्यायसंगत और सभी के लिए समावेशी विकास का परिणाम देने वाला साबित हुआ है। अमूल इसका बेहतरीन उदाहरण है। सहकारिता मंत्री के अनुसार, सरकार ने राष्ट्र के समतापूर्ण और समावेशी विकास के लिए अतीत में स्टार्टअप और अन्य उद्यमों को बढ़ावा दिया है और सहायता प्रदान की है।

भारत में 8.50 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जो 30 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 30 करोड़ सदस्यों को सेवा प्रदान करती हैं। ये सहकारी समितियां आत्मनिर्भरता, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। खासकर कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, बैंकिंग, आवास, उपभोक्ता सेवाओं, श्रम, चीनी आदि क्षेत्रों में। ये सहकारी समितियां निजी उद्यमों सहित अन्य खिलाड़ियों के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा करती हैं। नए क्षेत्रों को सहकारिता से जोड़ने से न सिर्फ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश के विकास में सहकारिता की भागीदारी भी बढ़ेगी। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहकारिता ही सबसे सशक्त माध्यम है। सहकारिता मंत्रालय की इस पहल से देश के युवाओं को रोजगार का एक और साधन उपलब्ध हो जाएगा। ■

देश की सभी पंचायतों में पैक्स के होने से मजबूत होगा कोऑपरेटिव आंदोलन

- देश में दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) बनाई जाएंगी और देश में एक भी पंचायत पैक्स से वंचित नहीं रहेगी
- लगभग तीन हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और एक हजार 70 मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) बनाए गए

सहकार जागरण टीम

मोदी सरकार ने कोऑपरेटिव मंत्रालय की स्थापना और उसके बाद से अब तक के साढ़े तीन वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने बहुत सारा काम किया है। सहकारिता के विकास के लिए सभी राज्यों को साथ लेकर सहकारिता डेटाबेस तैयार हुआ है, जिससे अब देश के सभी राज्यों, जिले और गांवों की सहकारी समितियों की जानकारी इस डेटाबेस में उपलब्ध है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में संसद में चर्चा के दौरान इन तथ्यों का जिक्र किया और कहा कि कंप्युटरीकरण से सहकारिता क्षेत्र में एक प्रकार से क्रांति आई है। देश के 67 हजार से अधिक पैक्स को कम्प्यूटर, सॉफ्टवेयर और डेटा स्टोरेज से जोड़ा गया है। आज इन 67,930 पैक्स में से 43,658 पैक्स कंप्युटर के माध्यम से काम कर रहे हैं। अब शाम को इनका अकाउंट मिला लिया जाता है और ऑनलाइन ऑडिट के साथ ही सारा कारोबार भी ऑनलाइन होता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारी समितियां रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) कार्यालय, राज्यों में रजिस्ट्रार कार्यालयों और ग्रामीण विकास बैंकों की शाखाओं का भी कंप्युटरीकरण किया गया और इसका पूरा खर्च भारत सरकार ने वहन किया। श्री शाह ने कहा कि पहली बार कोऑपरेटिव सेक्टर में सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसके सात प्रमुख पैरामीटर में पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, अर्बन कोऑपरेटिव, आवास क्रेडिट और खादी एवं ग्रामोद्योग समितियां शामिल होंगी। अब जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के अवार्ड दिए जाएंगे और रैंकिंग के हिसाब से कोऑपरेटिव बैंकों से उन्हें ऋण मिल सकेगा।

भारत में आठ लाख सहकारी समितियां हैं और 30 करोड़ देशवासी इनके सदस्य हैं। एक प्रकार से देश में हर चौथा व्यक्ति कोऑपरेटिव से जुड़ा है, लेकिन 75 साल से इसके विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। इससे देश में सहकारिता असमान रूप से चल रही थी और सहकारिता आंदोलन में विसंगतियां आने लगी थीं। श्री शाह ने खेद जताते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के साथ आयकर में बहुत अन्याय होता था। मोदी सरकार ने सहकारी समितियों के आयकर पर अधिभार को 12 से घटाकर सात प्रतिशत किया, न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को 18.5 से कम करके 15 प्रतिशत किया और दो लाख से कम के लेन-देन पर आयकर जुमार्ने से छूट प्रदान की। सरकार ने विनिर्माण करने वाली सहकारी समितियों को आयकर में रियायत देते हुए 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि पैक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए नकद जमा करने की सीमा को 20 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपए किया गया है। इसके साथ ही, सरकार ने टीडीएस से छूट की सीमा को एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए कर दिया है।

जल्द ही देश के सभी गांवों में होंगी सहकारी समितियां

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि देश में दो लाख नई प्राथमिक कृषि

ऋण समितियां (पैक्स) बनाई जाएंगी और देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं रहेगी जहां पैक्स नहीं होगा। दो लाख पैक्स के हर पंचायत में पहुंचने से हमारे देश का कोऑपरेटिव आंदोलन एक बार फिर संतुलित तरीके से खड़ा होगा। इसीलिए, मोदी सरकार ने पैक्स के बायलॉज बदलने का निर्णय लिया और कश्मीर से कन्याकुमारी और नॉर्थईस्ट से द्वारका तक पूरे देश ने मॉडल बायलॉज को स्वीकार किया। इसके माध्यम से 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों को पैक्स के साथ जोड़ा गया, चुनाव प्रक्रिया को जोड़ा गया और एक कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया, जो देश की सभी भाषाओं में है। उन्होंने कहा कि देश में 43 हजार पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) बन चुकें हैं जहां केंद्र और राज्य सरकार की 300 से अधिक योजनाओं के लाभ और सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्री शाह ने कहा कि देश में अब 36 हजार पैक्स पीएम समृद्धि केंद्र के रूप में काम करे रहे हैं, चार हजार पैक्स जनऔषधि केंद्र बन चुके हैं और 400 पैक्स पेट्रोल पंप भी चला रहे हैं। इस दौरान देश में लगभग तीन हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और एक हजार 70 मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) भी बनाए गए हैं। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग (जीइएम) पर खरीद के लिए 550 से अधिक सहकारी समितियां ऑनबोर्ड हो चुकी हैं।

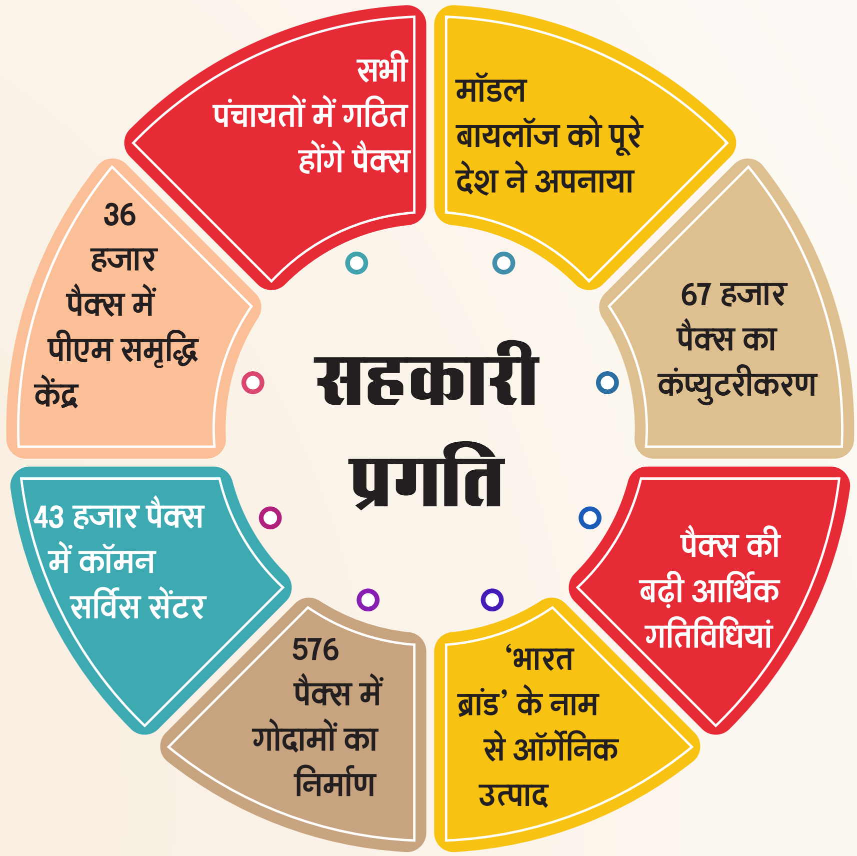

सहकारिता मंत्रालय से शुरू हुआ सहकारी विकास का नया अध्याय

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने किसानों, ग्रामीणों, कोऑपरेटिव नेताओं की दशकों से लंबित मांग को पूरा करते हुए साढ़े तीन साल पहले सहकारिता मंत्रालय का गठन किया, जिससे सहकारिता के विकास का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू हुई है और अब तक 11 पैक्स गोदाम बन चुके हैं और अपने खरीदे हुए धान और गेहूं को वहीं स्टोर कर रहे हैं। वहीं, 576 पैक्स गोदाम बनने का काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि वर्षों से दलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की मांग की जा रही थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार तीन दालों की शत प्रतिशत खरीद एमएसपी पर करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नैफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) की वेबसाइट पर रजिस्टर करने वालों को यह सुविधा मिलेगी। इसी तरह मक्के के किसानों को भी नाफेड और एनसीसीएफ की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, ताकि भारत सरकार उसकी एमएसपी पर शत प्रतिशत खरीद कर सके।

चीनी मिलों को आयकर की समस्या से मिली निजात

श्री शाह ने कहा कि पिछली सरकारों के समय बड़े-बड़े कोऑपरेटिव नेता कृषि मंत्री हुए, लेकिन सहकारी चीनी मिलों की आयकर की समस्या को दूर नहीं किया। वहीं, श्री मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सरकार ने 2022 में आयकर मूल्यांकन की समस्या हमेशा के लिए दूर कर दी। सहकारी चीनी मिलों को 2016 से लेकर 2022 तक 'इनकम टैक्स असेसमेंट' की जो दिक्कत थी, उसे मोदी सरकार ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सरकार ने चीनी मिलों की 4,600 करोड़ रुपए की डिमांड को पूरा किया और इससे हर साल आठ हजार करोड़ रुपए की नई डिमांड भी जेनरेट हुई। आजादी के बाद कोऑपरेटिव चीनी मिलों को शायद ही इतना बड़ा फायदा हुआ हो। उन्होंने कहा कि 84 मिलों को 10 हजार करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम में सहकारी चीनी मिलों की प्राथमिकता तय की गई। शीरा आधारित इथेनॉल संयंत्र और मल्टी फील्ड संयंत्र के लिए भी फाइनेंस की योजना शुरू की गई। सरकार ने शीरा पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटा कर पांच प्रतिशत कर दिया है।■

छत्तीसगढ़ में 33,700 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ कर बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी

आदिवासी समाज के विकास के लिए विशेष अभियान चला रहा केंद्र

- गरीब आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिंतित है सरकार
- छत्तीसगढ़ के तीन लाख गरीब परिवारों ने अपने नए घर में किया प्रवेश

सहकार जागरण टीम

छत्तीसगढ़ के लोगों से किए गए हर वादे को सरकार पूरा कर रही है। राज्य की महिलाओं और किसानों के कल्याण की वचनवद्धता को सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत पूरा किया है। किसानों को दो साल का लंबित बोनस दे दिया गया है और धान की खरीद भी बढ़ी हुई एमएसपी दरों पर हुई है। इससे लाखों किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। राज्य के विकास के प्रति सरकार की गंभीरता को बयां करने वाले इन विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिलासपुर में करोडों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के दौरान साझा किया। आदिवासी समाज के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण परिवारों के लिए उचित आवास सुलभ कराने और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा व जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए काम हो रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत तीन लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। 'धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान' की शुरूआत का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, जिससे राज्य के लगभग 7,000 आदिवासी गांवों को लाभ मिल रहा है। कमजोर आदिवासी समूहों की चुनौतियों को दूर करने के लिए 'पीएम जनमन योजना' के तहत राज्य के 18 जिलों में 2,000 से अधिक बस्तियों का विकास किया जा रहा है। देश के आदिवासी बस्तियों के लिए 5,000 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी की गई है, जिसमें से लगभग आधी सड़क छत्तीसगढ़ में ही बनाई जा रही हैं।

- 'धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान' के तहत आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा 80,000 करोड़ रुपए का निवेश, 7,000 आदिवासी गांवों को मिल रहा लाभ
- 'पीएम जनमन योजना' के तहत छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में 2,000 से अधिक बस्तियों का हो रहा विकास

गरीबों के लिए आवास, स्कूल, बिजली व गैस पर फोकस

बुनियादी ढांचे के विकास और लोगों की आजीविका को बढ़ाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप श्री मोदी ने 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। राज्य में विकास कार्यों को गति देने वाली इन परियोजनाओं में गरीबों के लिए आवास, स्कूल, सड़क, रेलवे, बिजली और गैस पाइपलाइन शामिल हैं। इनसे राज्य के नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि श्री विष्णु देव के नेतृत्व में पहला कैबिनेट निर्णय 18 लाख मकानों के

निर्माण का था, जिनमें से तीन लाख पूरे हो चुके हैं और बस्तर व सरगुजा के आदिवासी इलाकों के परिवारों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। इन घरों को शौचालय, बिजली, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और नल से जल जैसी आवश्यक सुविधाओं से लैस किए गए हैं और कहा कि इनमें से अधिकांश घर महिलाओं के स्वामित्व में हैं।

हमने इसे बनाया है और हम इसे विकसित करेंगे

श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी होने से राज्य सरकार वर्ष 2025 को 'अटल निर्माण वर्ष' के रूप में मना रही है। राज्य की जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा, 'हमने इसे बनाया है और हम इसे विकसित करेंगे।' उन्होंने राज्य की 50वीं वर्षगांठ तक देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया और कहा कि सरकार विकास का लाभ छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। सरकार ने लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी है और जीवन में सुविधाओं व अवसरों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। कई क्षेत्रों में रेल सेवाओं की शुरूआत का जिक्र कर श्री मोदी ने कहा कि वंचित क्षेत्रों में बिजली, पाइप से पानी और मोबाइल टावरों की सुविधा सुलभ हुई है। नए स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के निर्माण के जरिए छत्तीसगढ़ का परिदृश्य बदल रहा है।

विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाले राज्यों में से एक बना छत्तीसगढ़

राज्य में सस्ती व विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने और राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्ण विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाले राज्यों में से एक बनने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने इसे विकास की दिशा में मील का महत्वपूर्ण पत्थर कहा। राज्य में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। इस वर्ष के बजट में विभिन्न क्षेत्रों और पड़ोसी राज्यों में रेल संपर्क में सुधार के लिए सात 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए बिजली संयंत्र भी स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने सौर ऊर्जा पर सरकार के फोकस और 'पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना' की शुरूआत का जिक्र कर कहा कि इसका उद्देश्य बिजली के बिलों को खत्म करना और घरों को बिजली का उत्पादन करके आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। सरकार सौर पैनल लगाने के लिए प्रति घर 78,000 रुपए की सहायता कर रही है। राज्य में दो लाख से अधिक परिवार पहले ही इस योजना के लिए पंजीकरण करा चुके हैं।

आदिवासी अंचलों में शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाने पर जोर

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में 12,000 से अधिक आधुनिक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की गई है, जिनमें से 350 छत्तीसगढ़ में ही हैं। ये स्कूल दूसरों के लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे और राज्य की शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप श्री मोदी ने दो प्रमुख शैक्षिक पहल- राज्य के 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। उन्होंने राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया और इसे देश की शिक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में एकलव्य मॉडल स्कूलों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों को फिर से खोलने की सराहना की। इस पहल से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी।■

शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ कर रहा अंब्रेला संगठन 'नैफकब'

- जब भी कोई कोऑपरेटिव बैंक कमजोर पड़ेगा, नैफकब उसे वित्त प्रदान कर बंद होने से बचाएगा
- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के साथ जुड़े करीब आठ हजार पैक्स, हो रहा किसानों के उत्पादों का निर्यात

सहकार जागरण टीम

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (नैफकब) नाम से एक अंब्रेला संगठन बनाया गया है। जब भी कोई कोऑपरेटिव बैंक कमजोर पड़ेगा, नैफकब उसे वित्त प्रदान करेगा और उसे बंद होने से बचाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को पहले नए ब्रांच खोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के माध्यम से 10 प्रतिशत तक नई शाखाएं खोलने की अनुमति मिल गई है। यूसीबी को पहले लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उनके घर तक मुहैया कराने यानि 'डोरस्टेप बैंकिंग' की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब शहरी सहकारी बैंक 'डोर स्टेप बैंकिंग' की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों को पहले 'वन टाइम सेटलमेंट' की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब यूसीबी भी राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों की तरह 'वन टाइम सेटलमेंट' कर सकते हैं। सहकारी बैंकों के साथ भेदभाव का आलम यह था कि पहले आरबीआई में कोऑपरेटिव बैंकों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, पर वहां अब एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो कोऑपरेटिव बैंकों की समस्या की सुनवाई

- बीबीएसएसएल के माध्यम से देश के पारंपरिक व मीठे बीजों का संरक्षण एवं संग्रहण कर उन्हें किया जा रहा संरक्षित
- एनसीईएल के माध्यम से दुनियाभर के बाजारों में निर्यात की गई 12 लाख टन सामग्री, सीधे किसानों के खातों में जमा हो रहा मुनाफा

बीते तीन वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना भारत

श्री शाह ने कहा कि बीते तीन वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है। विश्व के कुल दूध उत्पादन का एक चौथाई उत्पादन भारत में होता है। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर लगभग 24 करोड़ टन हो गया है, जबकि वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा 14.6 करोड़ टन था। पिछले 10 साल में दूध उत्पादन 14.6 करोड़ टन से बढ़कर 24 करोड़ टन तक पहुंच गया है। वर्तमान समय में देश में 23 राष्ट्रीय और 240 जिला स्तरीय संघ हैं। इसके साथ ही 28 मार्केटिंग डेयरियां बनी हैं और दो लाख तीस हजार गांवों में प्राथमिक दूध उत्पादन समितियां भी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 के तहत दूध की खरीद मौजूदा 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 2028-29 में 1000 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। श्री शाह ने कहा कि अब सहकारी डेयरियां निजी तौर पर दूध बेचने वाले किसानों को पशु आहार उपलब्ध कराएंगी और उनके गोबर इकट्ठा कर कोऑपरेटिव डेयरियां गैस बनाने का काम करेंगी। सहकारी डेयरी ही पशुओं का टीकाकरण भी करेगी। उन्होंने कहा कि 10 हजार करोड़ रुपए के खर्च से इन सारी परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों में 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं और डेयरी में आर्थिक फायदा होने से महिला सशक्तिकरण भी होगा।

करेगा। श्री शाह ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 'होम लोन' की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। वाणिज्यिक रियल एस्टेट को भी ऋण देने की अनुमति दे दी गई है। गैर-अनुसूचित बैंकों को मजबूत बनाने के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। भारत सरकार ने डिपॉजिटरों का बीमा भी एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए तक कर दिया है, जिससे लोगों का कोऑपरेटिव बैंकों में विश्वास बढ़ा है।

श्री शाह ने कहा कि छोटा किसान और ग्रामीण व्यक्ति ऋण लेता है तो उसे ब्याज के साथ चुकता भी कर देता है। इसीलिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने जीरो एनपीए के साथ 90 हजार करोड़ रुपए का कारोबार किया है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी ने 44 समुद्री ट्रॉलर्स गुजरात और महाराष्ट्र के मछुआरों के लिए दिए हैं। देश के 48 सहकारी चीनी मीलों को एनसीडीसी ने 10 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। देश में सहकारिता को मजबूत करने में अहम भूमिका वाले एनसीडीसी ने ऋण में बढ़ोत्तरी और जीरो एनपीए रखने में सफलता हासिल की है और इसका मुनाफा 100 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव संस्था बनाया

सहकारिता मंत्रालय की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की तीन नई सहकारी समितियां स्थापित किया है जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के साथ लगभग आठ हजार पैक्स जुड़ चुके हैं और इनके माध्यम से किसानों का उत्पाद विदेश में निर्यात हो रहा है। एनसीईएल के माध्यम से दुनियाभर के बाजारों में 12 लाख टन सामग्री बेचकर इसका मुनाफा सीधा किसानों के खातों में जमा हुआ है। इसके साथ ही, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के माध्यम से हमारे पारंपरिक और मीठे बीजों का संरक्षण और संग्रहण कर उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) माध्यम से भारत ब्रांड के रूप में ऑर्गेनिक उत्पादों का प्रमाणीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'भारत ब्रांड' के नाम से देशभर में शत-प्रतिशत ऑर्गेनिक उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं।

'सहकारिता में सहकार' की पहल से सहकारी बैंकों में बढ़ रहा जन विश्वास

सहकारी क्षेत्र में समस्त धन का प्रवाह सहकारी बैंकों तक कराने के लिए गुजरात के पंचमहाल और बनासकांठा जिलों में 'सहकारिता में सहकार' की पहल की। इसके तहत सुनिश्चित किया कि हर सहकारी संस्था और सहकारी समिति के सदस्यों के बैंक अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में हों। 'सहकारिता में सहकार' की पहल के कारण गुजरात के बैंकों में हुई डिपॉजिट में लगभग आठ हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इन सब कदमों के कारण लोगों का सहकारी बैंकों में विश्वास बढ़ा है। श्री शाह ने कहा कि उन्होंने भी अपना अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में खुलवा लिया है। उन्होंने कहा कि वे 18 वर्ष की आयु से कोऑपरेटिव से जुड़े रहे हैं और इसकी खूबियों और कमियों का अनुभव किया है।■

छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि पर बोले श्री अमित शाह

छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किला नई पीढ़ी को स्वधर्म व स्वराज के लिए प्रेरित करता रहेगा

सहकार जागरण टीम

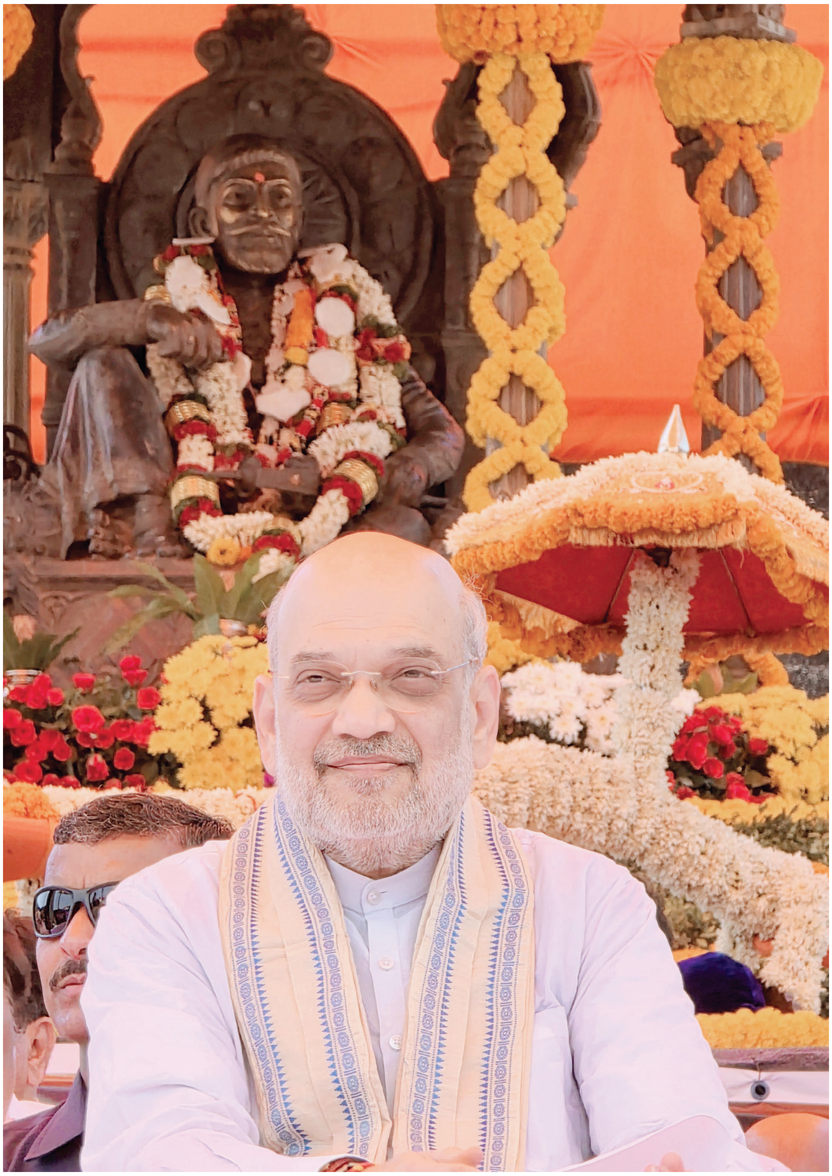

भारत को दुनिया में हर क्षेत्र में प्रथम बनाने की मूल कल्पना शिवाजी महाराज ने रखी थी। देश की आजादी के 75 वर्षों के बाद हम दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े हैं और संकल्प करते हैं कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब भारत दुनिया में हर क्षेत्र में प्रथम स्थान पर होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन संकल्पों को छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि के मौके पर महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पर आयोजित समारोह में साझा किया। श्री शाह ने कहा कि यह ऐतिहासिक किला बाल शिवा से लेकर छत्रपति के अंतिम समय तक के इतिहास का साक्षी है। शिवाजी महाराज ने हिन्दुस्तान के कण-कण में स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की एक अमर जिजीविषा पैदा की। देखते ही देखते चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ महाराष्ट्र हिन्दवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही वर्षों में अटक से कटक तक, बंगाल और दक्षिण में तमिलनाडु समेत पूरे देश में स्वराज का स्वप्न सफल होता दिखाई दिया।

श्री शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज का मतलब संकल्प, समर्पण, बलिदान, शौर्य, स्वाभिमान और स्वराज की अमर जिजीविषा है। स्वधर्म पर अभिमान, स्वराज की आकांक्षा और स्वभाषा को अमर बनाने के विचार मानव जीवन के स्वाभिमान के साथ जुड़े हैं। मानव जीवन के स्वाभिमान के इन तीन मूल चरित्र को शिवाजी महाराज ने देश और दुनिया के सामने रखा। उन्होंने यह सब ऐसे समय में किया जब आक्रान्ताओं से पराजय के कारण देश में गुलामी की मानसिकता पैदा हो गई थी। उनके जन्म के समय देश की जनता घोर अंधकार में डूबी थी और ऐसा वातावरण था कि किसी के मन में स्वराज की कल्पना का आना भी दुष्कर था। देवगिरी के पतन के बाद 100 साल के अंदर

ही महाराष्ट्र से लेकर समग्र दक्षिण का पतन हुआ और धीरे-धीरे स्वधर्म और स्वराज की बात को लोग गुनाह समझने लगे थे। लेकिन, ऐसे समय में माता जीजाबाई की प्रेरणा से 12 साल के होनहार बालक शिवाजी ने सिन्धु से कन्याकुमारी तक एक बार फिर भगवा फहराने की प्रतिज्ञा की। शिवाजी ने गुलामी की मानसिकता को तोड़कर फिर से हिन्दवी साम्राज्य को स्थापित किया। श्री शाह ने कहा कि ऐसी दृढ़ इच्छाशक्ति, अदम्य साहस, अकल्पनीय रणनीति और समाज के हर वर्ग को साथ रखकर एक अपराजेय सेना का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा किसी और ने नहीं किया।

श्री शाह ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ न भाग्य था, न अतीत ही उनके साथ था और न ही धन एवं सेना उनके पास थी, लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ पूरे देश को स्वराज का मंत्र दिया और देखते ही देखते 200 वर्षों से चल रही मुगलशाही को चकनाचूर कर दिया। जब शिवाजी महाराज की सेना अटक, बंगाल, कटक और तमिलनाडु तक पहुंची, तब सभी को भरोसा हुआ कि देश, स्वधर्म एवं हमारी भाषाएं और संस्कृति बच गई हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित देश के हर बच्चे को पढ़ाया जाए

श्री शाह ने कहा कि राजमाता जीजाबाई ने न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, बल्कि उन्हें स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरोद्धार करने की प्रेरणा भी दी। बालक शिवाजी को कम उम्र में ही समग्र देश को स्वतंत्र कराने और हिन्दवी साम्राज्य का संस्थापक बनाने का विचार भी माताजी ने ही दिया। उनके दिए संस्कारों को ही शिवाजी ने विशाल वटवृक्ष का रूप दिया। शिवाजी के बाद संभाजी महाराज, महारानी ताराबाई, संताजी और तानाजी मुगल शासक औरंगजेब के जिंदा रहने तक उससे लड़ते और जूझते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि अपने आप को आलमगीर कहने वाला भी महाराष्ट्र में हार

गया और उसकी समाधि भी यहीं है।

श्री शाह ने कहा कि हमारा दायित्व है कि भारत के हर बच्चे को शिवचरित पढ़ाया जाए। शिवराय यानि शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, संपूर्ण देश में पढ़ाया जाए जिससे कि पूरा देश और पूरी दुनिया उनसे प्रेरणा ले सके।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने काम से सुशासन स्थापित किए

श्री शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज ने प्रशासन के क्षेत्र में ढेर सारे सिद्धांत स्थापित किए। उनके अष्ट प्रधान मंडल की कल्पना को हमने कैबिनेट के रूप में अपनाया। उन्होंने कहा कि अपने काम से सुशासन का दृष्टांत स्थापित करके शिवाजी ने सत्तासीन लोगों को न्याय के लिए भी कई सिद्धांत दिए। श्री शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज का अंतिम संदेश था कि स्वराज, स्वधर्म के सम्मान और स्वभाषा को अमर बनाने की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में यह लड़ाई गौरव के साथ आगे बढ़ रही है और भारत को पूरे विश्व में गौरवमय स्थान बना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शिवाजी महाराज की राज मुद्रा को हमारी नौसेना का प्रतीक बनाकर पूरी दुनिया में घोषणा की है कि हमारा देश और हमारा स्वराज पूरी तरह सुरक्षित है। श्री शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज ने काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्धार, सभी ज्योतिर्लिंगों तक पहुंचने और राम जन्मभूमि का उद्धार करने को कहा था और यह सारे कार्य श्री मोदी के कार्यकाल में हुए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर मोदी सरकार ने औरंगजेब द्वारा तोड़े गए काशी विश्वनाथ मंदिर को पुनर्जीवित किया है। श्री शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज के संदेश को पूरा करने में जो कुछ बाकी है, उसे पूरा करने के लिए पूरा देश कटिबद्ध है। महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी को घर-घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। यहां के 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं।■

भारत के विकास मॉडल को स्वीकार कर रही दुनिया: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

सहकार जागरण टीम

- **10 वर्षों पहले तक दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत पिछले सात-आठ वर्षों में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया**
- **अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, हर घर तक पहुंच गई है ऑनलाइन बैंकिंग**

वर्ष 2047 तक हम एक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और देश के युवा तेजी से कौशल प्राप्त कर रहे हैं। इससे नवाचारों को गति मिल रही है। इन विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एक कार्यक्रम में साझा किया। उन्होंने विश्वास जताया कि देश की युवा शक्ति विकसित भारत अभियान को गति और दिशा प्रदान करेगी। देश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी के 70 सालों के बाद दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत पिछले सात-आठ वर्षों में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

एक वैश्विक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसने पिछले 10 साल में अपनी जीडीपी को दोगुना किया है। भारत ने इन वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था में दो लाख करोड़ डॉलर जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के मजबूत होने से देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और इससे नया 'मध्यम वर्ग' बना है। यह नव-मध्यम वर्ग सपनों और आकांक्षाओं के साथ एक नया जीवन शुरू कर रहा है और अर्थव्यवस्था में योगदान देकर इसे जीवंत बना रहा है।

सपनों का नहीं लक्ष्य पूरा करने वाला राष्ट्र है भारत

श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं, जिनमें से उनकी सरकार के करीब 11 साल राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने निर्भरता से आत्मनिर्भरता, आकांक्षाओं

से उपलब्धियों और हताशा से विकास की ओर बदलावों का जिक्र किया और कहा कि उनके सेवाकाल में लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। दुनिया भारत के विकास मॉडल की पहचान कर रही है और इसे स्वीकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत अब केवल 'सपनों का राष्ट्र' नहीं है, बल्कि 'ऐसा राष्ट्र है जो लक्ष्य पूरा करता है'।' उन्होंने कहा कि एक दशक पहले गांवों में शौचालयों की समस्या के कारण महिलाओं के पास सीमित विकल्प थे, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने इसका समाधान प्रदान किया। वर्ष 2013 में स्वास्थ्य सेवा के बारे में चर्चा महंगे उपचारों के इर्द-गिर्द घूमती थी, लेकिन अब आयुष्मान भारत अभियान ने इसका समाधान प्रस्तुत किया है। इसी तरह गरीबों की रसोई, जो कभी धुएं से भरी रहती थी, उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि 2013 में बैंक खातों के बारे में पूछे जाने पर महिलाएं अक्सर चुप रहती थीं, लेकिन जन धन योजना के कारण आज 30 करोड़ से अधिक महिलाओं के पास अपने खाते हैं। पीने के पानी की समस्या के कारण लोगों को कभी कुओं और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसे हर घर नल से जल योजना के जरिए हल किया गया है।

'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' से मिली बड़ी सफलता

श्री मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव की चर्चा की, जिसने विनिर्माण क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है। उन्होंने कहा कि जहां दुनिया कभी भारत को वैश्विक बाजार के रूप में देखती थी, वहीं अब वह देश की एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में पहचान करती है। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित होने से भारत में चिकित्सा निदान की लागत काफी कम हो जाएगी। भारत के मोबाइल फोन उद्योग की सफलता की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्यात 2014-15 में एक बिलियन डॉलर से भी कम से बढ़कर एक दशक के भीतर बीस बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने वैश्विक दूरसंचार और नेटवर्किंग उद्योग में एक शक्ति केंद्र के रूप में भारत के उभरने और ऑटोमोटिव सेक्टर में निर्यात में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले भारत मोटर साइकिल के पुर्जे बड़ी मात्रा में आयात करता था, लेकिन अब भारत में निर्मित पुर्जे यूएई और जर्मनी जैसे देशों में पहुंच रहे हैं। सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी सौर सेल और मॉड्यूल के आयात में कमी आई है और निर्यात में 23 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने रक्षा निर्यात में वृद्धि पर भी जोर देकर कहा कि पिछले 10 वर्षों में यह 21 गुना बढ़ा है। ये उपलब्धियां भारत की विनिर्माण अर्थव्यवस्था की ताकत और विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित करने की इसकी क्षमता को दर्शाती हैं।

नीतिगत सुधारों जनता को परेशानियों से राहत मिली

- अब देश में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 77 से बढ़कर 550 से अधिक हो गई है।
- पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए पहले 50 दिनों तक का प्रतीक्षा समय अब घटकर केवल 5-6 दिन रह गया है।
- सरकार ने अपनी प्रासंगिकता खो चुके लगभग 1,500 वर्षों पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया है।
- करीब 40,000 अनुपालनों को हटा दिया है।
- इन उपायों से जहां एक ओर जनता को परेशानियों से राहत मिली, वहीं सरकारी तंत्र के भीतर ऊर्जा का संरक्षण हुआ।

बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलावों से मिली बड़ी उपलब्धियां

श्री मोदी ने कहा कि 50-60 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुलभ बैंकिंग सेवाओं के वादे के साथ किया गया था, लेकिन लाखों गांवों में ऐसी सुविधाओं का अभाव था। लेकिन, अब यह स्थिति बदल गई है और ऑनलाइन बैंकिंग हर घर तक पहुंच गई है। आज देश में हर पांच किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग सुविधा केंद्र है। सरकार ने न केवल बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली को भी मजबूत किया है। बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में काफी कमी आई है और उनका मुनाफा 1.4 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा लूटने वालों को अब जवाबदेह ठहराया जा रहा है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है और इसे कानूनी तौर पर उन पीड़ितों को वापस किया जा रहा है, जिनसे यह ले लिया गया था।

सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए सरकार ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) प्लेटफॉर्म पेश किया है, जहां सरकारी विभाग अपनी आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करते हैं और विक्रेता बोलियां लगाते हैं। सरकार को इस पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार पर लगाम लगने में सफलता मिल रही है और अब तक एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। श्री मोदी ने भारत की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली की वैश्विक मान्यता पर भी जोर देते हुए कहा कि डीबीटी ने करदाताओं के तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि को गलत हाथों में जाने से रोका है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे 10 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थियों को आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया है।■

असम के डेरगांव में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का लोकार्पण कर बोले श्री शाह

काशी की तरह पूर्वोत्तर की पुलिसिंग का तीर्थ बनेगी नई अकादमी

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के साथ ही असम राज्य भी विकास के रास्ते पर आगे बढ रहा है। एक जमाने में जिस असम में आंदोलन, उग्रवाद और गोलीबारी की चर्चा होती थी, वहां अब सबसे आधुनिक 27 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगने का काम शुरू हो चुका है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने असम के डेरगांव में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का लोकार्पण के मौके पर इन तथ्यों को बयां किया और कहा कि मोदी

- **जिस असम में पहले केवल आंदोलन, उग्रवाद व गोलीबारी की चर्चा होती थी, वहां 27 हजार करोड़ रुपए लागत वाली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लग रही है**
- **आठ लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं के माध्यम से असम में स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार**

सरकार ने असम में सिर्फ शांति लाने का प्रयास ही नहीं किया है, बल्कि राज्य में शांति लाकर दिखाया भी है। सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और अब मुख्यमंत्री हिंमता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में पांच लाख करोड़ का निवेश भी राज्य में आ रहा है, जो यहां के युवाओं के लिए स्वर्णिम भविष्य की नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कई शांति समझौते हुए हैं, जिनमें 2020 में असम-बोड़ोलैंड समझौता, 2021 में कार्बी आंगलोंग समझौता, 2022 में आदिवासी शांति समझौता, 2023 में उल्फा, असम मेघालय और असम-अरुणाचल समझौते हुए। इन शांति समझौतों के कारण 10 हजार से ज्यादा युवा हथियार डालकर विकास की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। डबल इंजन सरकार

ने असम में अपराध दोष सिद्धि अनुपात पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत पहुंचाया है। असम में पहले जो पुलिस केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तक सीमित थी, अब वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और तीन नए आपराधिक कानूनों पर सफल अमल के लिए काम कर रही है।

राज्य में गरीब कल्याण की दिशा में सरकार की बड़ी पहल

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार और असम सरकार ने गरीब कल्याण के बहुत से काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 58 लाख घरों में पहली बार नल से जल पहुंचाया, एक करोड़ 80 लाख लोगों को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज दिया, 43 लाख घरों में शौचालय बनाए, दो करोड़ 32 लाख गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो चावल मुफ्त दिया, 51 लाख गैस सिलेंडर वितरित किए और गरीबों को 21 लाख घर देने का काम भी भारत सरकार और असम सरकार ने किया है। श्री शाह ने कहा कि पिछली सरकार के 10 साल के शासन में असम को एक लाख 27 हजार करोड़ रुपए का 'वितरण अनुदान' और 'ग्रांट-इन-एड' मिला, जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में चार गुना बढ़ाकर चार लाख 49 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कई सालों तक असम को दंगों की आग में झोंका, ग्रांट नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और शांति भी नहीं आने दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, शांति भी आई है और कई प्रकार के उद्योग भी लग रहे हैं।

विकास कार्यों से बदल रही राज्य की तस्वीर

श्री शाह ने कहा कि भारत सरकार ने 10 हजार करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतमाला परियोजना, तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से धुबरी-फुलवाड़ी पुल, 3,400 करोड़ रुपए की लागत से सिलचर-चुराईबाड़ी कॉरिडोर को फोर लेन करने और एक हजार करोड़ रुपए की लागत से माजुली द्वीप पर नया तटबंध और सड़क बनाने जैसे कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर छह लेन पुल का काम निमार्णाधीन है और 382 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 715-के पर माजुली और जोरहट को जोड़ा जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि 1,200 करोड़ रुपए की लागत से गोपीनाथ जी के नाम से एयरपोर्ट का विस्तार, रेलवे क्षेत्र में 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण, एक हजार करोड़ रुपए की लागत से एम्स और तुमुलपुर, कोकराझार, नलबारी एवं धुबरी मे मेडिकल कॉलेज जैसे बहुत से बुनियादी विकास के काम श्री मोदी के नेतृत्व में हुए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में असम में निवेश के लिए हुए सम्मेलन में पांच लाख 18 हजार करोड़ के समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर समझौता ज्ञापन (एमओयू) जमीन पर उतरेंगे। भारत सरकार भी असम के विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। श्री शाह ने कहा कि आठ लाख करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट्स से यहां के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।■

पूर्वोत्तर में शांति की एक नई शुरूआत

श्री शाह ने कहा कि लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी के रूप में जो बीज बोया जा रहा है, एक दिन वह बहुत बड़ा वटवृक्ष बन पूरे देश की पुलिसिंग को छाया देगा। यह एकेडमी न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की पुलिसिंग के लिए काशी के समान एक तीर्थ बनेगी और यहीं से शांति की एक नई शुरूआत होगी। उन्होंने शाह ने कहा कि असम के वीर सेनानी और सपूत लचित बोरफुकन जी ने असम को मुगलों के खिलाफ विजय दिलाई थी। असम के वीर सपूत और महान योद्धा लचित बोरफुकन को पहले सिर्फ असम तक सीमित रखा गया था, लेकिन अब उनकी जीवनी 23 भाषाओं में देशभर के पुस्तकालयों में उपलब्ध है। इससे उनके बारे में पूरे देश की जनता को जानने और उनसे प्रेरणा पाने का अवसर मिलेगा। श्री शाह ने कहा कि लचित बोरफुकन अकादमी का पहला चरण 167 करोड़ खर्च की लागत से पूरा किया गया है और तीनों चरणों पर कुल 1050 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस अकादमी में कई प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और यह अकादमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस अकादमी बनेगी। उन्होंने कहा कि पहले असम की पुलिस अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए जाती थी, लेकिन पिछले आठ वर्षों में राज्य के शासन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि अब इस पुलिस अकादमी में गोवा और मणिपुर के दो हजार पुलिसकर्मियों ने ट्रेनिंग ली है। अगले पांच वर्षों में देशभर की पुलिस अकादमियों में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी प्रथम स्थान पर होगी।

'मन की बात' के 120वें एपिसोड में बोले पीएम श्री नरेन्द्र मोदी

'कैच द रेन' अभियान के लिए एक बार फिर देश ने कस ली कमर

सहकार जागरण टीम

▶▶ **जलशक्ति मंत्रालय और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों से जल संरक्षण कार्यों में आई तेजी**

▶▶ **ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुहिम से जोड़ने के लिए चलाया जा रहा जल संचय जन-भागीदारी अभियान**

गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर-शहर, गांव-गांव पानी बचाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जलशक्ति मंत्रालय और अलग-अलग स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी। 'मन की बात' के 120वें एपिसोड में उन्होंने बताया कि अनेक राज्यों में जल संरक्षण से जुड़े कामों ने नई तेजी पकड़ी है। देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, सामुदायिक सोख्ता का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी 'कैच द रेन' अभियान के लिए कमर कस ली गई है। जल संरक्षण से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन-भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार का प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं, उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है।

'मन की बात' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इस अभियान के तहत देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। पिछले 7-8 साल में नए बने टैंक, तालाब और भूजल को रिचार्ज करने के अन्य ढांचों से 11 अरब घन मीटर से भी ज्यादा पानी का संरक्षण हुआ है। यह पानी भाखड़ा नांगल बांध में जमा पानी से ज्यादा है। इस बांध का पानी गोविंद सागर झील का निर्माण करता है जिसकी लंबाई ही 90 किलोमीटर से ज्यादा है। इस झील में 9-10 अरब घन मीटर से

ज्यादा पानी संरक्षित नहीं हो सकता है। देशवासियों ने अपने छोटे-छोटे प्रयास से देश के अलग-अलग हिस्सों में 11 अरब घन मीटर पानी के संरक्षण का इंतजाम कर दिया है। ये शानदार प्रयास है।'

जल संरक्षण की दिशा में कर्नाटक के गडग जिले के लोगों द्वारा किए गए प्रयास की प्रधानमंत्री ने सराहना की। कुछ साल पहले यहां के दो गांव की झीलें पूरी तरह सूख गईं। एक समय ऐसा भी आया जब पशुओं के पीने के लिए भी पानी नहीं बचा। धीरे-धीरे झील घास-फूस और झाड़ियों से भर गई। गांव के कुछ लोगों ने झील को पुनर्जीवित करने का फैसला किया और इस काम में जुट गए। ग्रामीओं के प्रयास देखकर आसपास की सामाजिक संस्थाएं भी उनसे जुड़ गईं। सब लोगों ने मिलकर कचरा और कीचड़ साफ किया और कुछ समय बाद झील बिल्कुल साफ हो गई। अब लोगों को इंतजार है बारिश के मौसम का। यह 'कैच द रेन' अभियान का शानदार उदाहरण है। श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से ऐसे सामुदायिक प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अभी से योजना बनाइये और हो सके तो गर्मियों में अपने घर के आगे मटके में ठंडा जल जरूर रखिए। घर की छत पर या बरामदे में पक्षियों के लिए भी पानी रखने का उन्होंने सुझाव दिया।

खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'कुछ दिन पहले ही संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना लोकप्रिय हो रहा है। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए मैं बधाई देता हूँ। हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 महिला खिलाड़ियों के नाम रहे।'

अपने संबोधन में श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित हुए एक और भव्य आयोजन के बारे में बताया जिसने लोगों को बहुत प्रेरणा दी और जोश से भर दिया है। इनोवेटिव आइडिया के रूप में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के करीब 25 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। इन सभी का एक ही लक्ष्य था- फिट रहना और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में शामिल लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ-साथ पोषण से जुड़ी जानकारियां भी मिलीं। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में भी इस तरह के कार्निवल का आयोजन करें। इस पहल में माई-भारत बहुत मददगार बन सकता है।

'मन की बात' में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासियों की उपलब्धियों के साथ ही अक्सर सामाजिक विषयों को भी उठाते हैं। कई बार चुनौतियों पर भी चर्चा करते हैं। 'मन की बात' के 120वें एपिसोड में उन्होंने टेक्सटाइल वेस्ट से जुड़ी चुनौतियों की चर्चा की। उन्होंने कहा, 'टेक्सटाइल वेस्ट पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। आजकल दुनियाभर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। जो पुराने कपड़े आप पहनना छोड़ देते हैं, वही टेक्सटाइल वेस्ट बन जाता है। इस विषय में बहुत सारी ग्लोबल रिसर्च हो रही है। एक रिसर्च में यह सामने आया है कि एक प्रतिशत से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकल किया जाता है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है, जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है यानि चुनौती बहुत बड़ी है।'

प्रधानमंत्री के मुताबिक, इस चुनौती से निपटने के लिए देश में कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी पर काम शुरू किया है। कई युवा सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुड़े हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते-चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं आजकल 'सर्कुलर फैशन ब्रांड' को लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। नए-नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से निपटने में कुछ शहर भी अपनी नई पहचान बना रहे हैं। हरियाणा का पानीपत टेक्सटाइल रिसाइक्लिंग के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। बेंगलुरू भी नवाचार आधारित तकनीक समाधान से अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यहां आधे से ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट को जमा किया जाता है। इसी तरह, तमिलनाडु का तिरुपुर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट में जुटा हुआ है।■

आबसू के 57वें वार्षिक सम्मेलन में बोले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

बोडोलैंड में शांति स्थापित करने में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की महत्वपूर्ण भूमिका

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पूरे पूर्वोत्तर को उग्रवाद, आंदोलन, ब्लॉकेड, बंद और हिंसा जैसी समस्याओं से मुक्त करा कर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। जब बोडो समझौता हुआ, तब केवल बोडोलैंड और असम ही नहीं, बल्कि पूरा देश खुश हुआ। इन तथ्यों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कोकराझार, असम में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (आबसू) के 57वें वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर साझा किया। उन्होंने कहा कि बोडोलैंड क्षेत्र में कायम शांति, विकास और उत्साह में आबसू की महत्वपूर्ण भूमिका है। आबसू की भागीदारी के बिना बोडो शांति समझौता संभव नहीं हो पाता और न ही बोडोलैंड में शांति स्थापित हो पाती।

श्री शाह ने कहा कि जिस तरह बोडोलैंड के लोग देश से प्यार करते हैं, उसी तरह पूरा देश बोडोलैंड और यहां के लोगों से प्यार करता है और यहां के युवाओं के विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और असम सरकार बोडोलैंड के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। श्री शाह ने बोडोलैंड में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का संकल्प जताया, जिससे बोडो युवा विश्व के युवाओं से प्रतिस्पर्धा कर सकें। बोडो युवाओं से पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देने और शांति प्रक्रिया को स्थापित करने में योगदान देने की अपील करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में हाल में इनवेस्टमेंट समिट हुई, जिससे पांच लाख करोड़ रुपए का निवेश असम में आ रहा है।

- **बोडोलैंड में पहले उन्माद, उत्पात और अलगाववाद की बात होती थी, अब शिक्षा, विकास और उद्योग की बात होती है**
- **मोदी सरकार अगले दो वर्षों में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) शांति समझौते को शत-प्रतिशत क्रियान्वित करेगी**

रोजगार और कौशल विकास पर सरकार का जोर

श्री शाह ने कहा कि रोजगार और कौशल विकास के लिए भी ढेर सारे काम किए गए हैं। व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) और आवर्ती जमा (आरडी), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), पशुपालन, मत्स्यपालन और बागवानी सहित सभी क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों को साथ रखकर स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाया है। आबसू शिक्षा, सशक्तिकरण और विकास को आगे ले जा रहा है और आबसू के प्रयास से ही अब बोडो भाषा माध्यम से विद्यार्थी 12वीं तक की परीक्षा दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोडो भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल है और वर्षों तक जीवित रहेगी। सैकड़ों युवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाया गया है। पिछले तीन सालों में असम में नेशनल डेमक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के 4881 सदस्यों के पुनर्वास पर 287 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसका 90 प्रतिशत हिस्सा मोदी सरकार ने दिया है। श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी

- अब दिल्ली में भी मिल रहा है 'मशरूम फ्रॉम बोडोलैंड', बोडोलैंड के एक दर्जन से अधिक उत्पादों को मिला जीआई टैग
- 8 400 बोडो युवाओं को असम कमांडो बटालियन में भर्ती से हुई एक नई शुरूआत

बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा के हर स्वप्न को धरातल पर उतारेगी सरकार

श्री शाह ने उन पांच हजार शहीदों को भी याद किया, जिन्होंने संघर्ष करके बोडोलैंड की शांति को प्रस्थापित करने का निर्णय किया। जब पूरा बोडोलैंड अपने नेता बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा के बताए रास्ते पर चल रहा है, ऐसे समय में केंद्र सरकार ने दिल्ली में एक प्रमुख सड़क का नामकरण बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा के नाम पर करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार और असम सरकार बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मा के हर स्वप्न को धरातल पर उतारेगी। बोडोलैंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मात्र 35 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र की भाषा बोडो को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया और सोनितपुर और बिश्वनाथ जिले को बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) में शामिल कर क्षेत्र का विस्तार किया गया।

के नेतृत्व में भारत सरकार ने असम में कुल नौ उग्रवादी संगठनों से समझौते करके 10,000 से ज्यादा युवाओं को समाज की मुख्यधारा में शामिल किया है। असम सरकार ने 400 बोडो युवाओं को असम कमांडो बटालियन में भर्ती करके एक नई शुरूआत की है।

बोडोलैंड के एक दर्जन से अधिक उत्पादों को जीआई टैग

श्री शाह ने कहा कि 27 जनवरी 2020 को जब बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो विपक्ष मजाक उड़ा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार और असम सरकार ने इस समझौते की 82 प्रतिशत शर्तों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार अगले दो वर्षों में इस समझौते को शत-प्रतिशत क्रियान्वित कर देगी। इसके बाद बीटीआर में चिरकालिक शांति होगी। श्री शाह ने कहा कि बीटीआर शांति समझौते के तहत सरकार ने एक अप्रैल 2022 को पूरे बीटीआर क्षेत्र से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (एफएसपीए) हटा लिया।

भारत सरकार के 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) कार्यक्रम के तहत दिल्ली के होटलों में कोकराझार का मशरूम 'बोडोलैंड से मशरूम' के नाम से सबके व्यंजनों में शामिल हो रहा है। बोडोलैंड के एक दर्जन से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है और इससे पूरे बीटीआर क्षेत्र में धीरे-धीरे औद्योगिक वातावरण बन रहा है। यह बोडोलैंड में कायम शांति के कारण ही संभव हो सका है। शांति होने के कारण ही बोडोलैंड ने 'डुरंड कप' टूर्नामेंट की मेजबानी की। श्री शाह ने बोडोलैंड के खिलाड़ियों से अपील की कि वे वर्ष 2036 में भारत में संभावित ओलंपिक के लिए आवश्यक तैयारियों में जुट जाएं।

एक जमाने में जहां बोडोलैंड क्षेत्र में चलती थीं गोलियां, वहां तिरंगा लहरा रहे हैं बोडो युवा

श्री अमित शाह ने कहा कि एक जमाना था जब बोडोलैंड में उन्माद, उत्पात और अलगाववाद की बात होती थी, लेकिन अब शिक्षा, विकास और उद्योग की बात होती है। एक जमाने में जहां गोलियां चलती थीं, वहां अब बोडो युवा हाथों में तिरंगा लहरा रहे हैं। यह दृश्य पूरे देश के लिए एक संदेश है।

उन्होंने कहा कि बोडोलैंड के लोगों द्वारा माने जाने वाले बाथो धर्म में बहुत ऊंचाई है। बाथो दो धातुओं के मेल से बना है, जिसका अर्थ 'पंचतत्व के निमार्ता का गहरा रहस्य' है। पंचतत्व में अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल शामिल हैं और यही इस महान धर्म की नींव हैं। श्री शाह ने कहा कि वे स्वयं भी बाथो धर्म के संदेश को प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। ■

मिजोरम के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बोले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

मिजोरमवासियों की तीन दशक पुरानी मांग हुई पूरी

- **आइजॉल में असम राइफल्स की भूमि का मिजोरम सरकार को हस्तांतरण**
- **विकसित, शांत, सुरक्षित और सुंदर मिजोरम के लिए कटिबद्ध है मोदी सरकार**

सहकार जागरण टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पिछले 10 वर्षों से पूरे नॉर्थईस्ट को मजबूत और एकजुट करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। भारत सरकार नॉर्थईस्ट में टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, स्पोर्ट्स से लेकर अंतरिक्ष तक, कृषि से लेकर उद्यमिता तक, हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम गढ़ रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन तथ्यों को मिजोरम के आइजॉल में असम राइफल्स बटालियन की भूमि का मिजोरम सरकार को हस्तांतरण और नक्शों के औपचारिक आदान-प्रदान के मौके पर साझा किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम मिजोरम के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। करीब 35 साल से विशिष्ट प्रकार की भौगोलिक स्थिति और जगह की कमी के कारण बहुत समय से यह मांग थी कि आइजॉल सहित पूरे मिजोरम के विकास के लिए असम राइफल्स को भीतरी हिस्से में भेजा जाए।

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी के दूरदर्शी और महत्वपूर्ण निर्णय के कारण जनता की यह मांग पूरी हो रही है और मिजोरम के प्रमुख एरिया में बड़ी भूमि उपलब्ध हो रही है, जिससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है बल्कि मिजोरम की जनता के प्रति मोदी सरकार की ज़िम्मेदारी का प्रतीक है। यह निर्णय मिजोरम के विकास के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक है। श्री शाह ने कहा कि 1890 में आइजॉल में सेना का पहला कैंप बनने से लेकर अबतक के इतिहास में यह सबसे बड़ा निर्णय माना जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2014 से अबतक 78 बार नॉर्थईस्ट का दौरा किया

श्री शाह ने कहा कि देश की आजादी के समय से वर्ष 2014 तक देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने कुल 21 बार नॉर्थईस्ट का दौरा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री मोदी वर्ष 2014 से अबतक 78 बार पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। नॉर्थईस्ट के मंत्रियों के अलावा वर्ष 2014 से पहले अन्य मंत्रियों ने नॉर्थईस्ट का कुल 71 बार दौरा किया था, जबकि पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय मंत्रियों ने 700 से अधिक बार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए यात्रा की।

श्री शाह ने कहा कि नॉर्थईस्ट में विकास तो हो ही रहा है, वहीं इसके साथ ही श्री मोदी ने पूर्वोत्तर में अभूतपूर्व शांति भी स्थापित किया है। एक विकसित, शांत, सुरक्षित और सुंदर मिजोरम के लिए भारत सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। सरकार ने मिजोरम में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 502-ए पर एक पैकेज-1 और पैकेज-3 शुरू किए गए हैं। आइजॉल और कोलासिब ज़िलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर 1,742 करोड़ रुपए की लागत से फोर लेन रोड का निर्माण हुआ है, 1600 करोड़ रुपए से आइजॉल-तुइपंग राष्ट्रीय राजमार्ग 54 को डबल लेन करने का काम और मिजोरम में अनेक स्थानों पर 100 करोड़ रुपए की लागत से बांस के लिंक रोड शुरू करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि दो करोड़ रुपए की लागत से 10 हैलीपैड बनाए गए हैं। पांच हजार करोड़ रुपए की लागत से बैराबी-सैरांग रेलवे को शुरू किया गया है। 600 करोड़ रुपए की लागत से 164 बिस्तर वाला सुपर स्पेशियलिटी रिसर्च सेंटर आज मिजोरम में बन रहा है। 1,300 करोड़ रुपए की लागत से तुइरियल हाइड्रो पावर परियोजना भी शुरू की गई है। इसके अलावा 214 मोबाइल टावर लगाकर मोबाइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने का काम किया गया है।■

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी से स्वर्णिम होगा सहकारिता का भविष्य

श्री दिलीप संघाणी

भारत में सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सरकार ने 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय' की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। विधेयक के संसद से दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने जाने से अब यह सपना साकार हो चुका है। यह विश्वविद्यालय न केवल सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि सहकारी क्षेत्र को अधिक पेशेवर व प्रभावी बनाने में भी मदद करेगा और सहकारी आंदोलन के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। यह संस्थान सहकारी शिक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जिससे सहकारी संस्थानों का कार्य अधिक पेशेवर, आधुनिक और प्रभावी हो सकेगा। यह युवाओं को एक वैकल्पिक और आकर्षक करियर विकल्प प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को सहकारी संस्थाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे यह एक आकर्षक करियर विकल्प बनेगा।

सहकारी क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा देकर यह विश्वविद्यालय युवाओं को सहकारी प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, सहकारी विपणन, डिजिटल सहकारिता और अन्य विषयों में विशेष शिक्षा प्रदान करेगा। पेशेवर प्रशिक्षण और नवीनतम शोध के माध्यम से सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा। डिजिटल तकनीकों, डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से सहकारी संस्थानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठनों के साथ साझेदारी कर भारतीय सहकारी क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक

बनाएगा।

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी सहकारी क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला पहला संस्थान होगा। इसके पाठ्यक्रम विशेष रूप से व्यावहारिक और रोजगारोन्मुख होंगे, जिनमें शामिल होंगेः

सहकारी प्रबंधन : सहकारी संस्थानों के सुचारू संचालन और नेतृत्व कौशल।

सहकारी वित्त : सहकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए पेशेवर ट्रेनिंग।

डिजिटल सहकारिता : सहकारी क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का समावेश।

सामुदायिक विकास और सहकारिता : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देना।

कृषि और ग्रामीण सहकारिता : कृषि आधारित सहकारी समितियों को आधुनिक बनाने के लिए।

सहकारी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण

सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए शोध और प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विभिन्न राज्यों और देशों में सहकारी नीतियों का अध्ययन कर भारत के लिए उपयुक्त सहकारी नीतियों पर अनुसंधान करेगा। सहकारी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और प्रबंधकों के लिए समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

सहकारी आंदोलन और 'विकसित भारत' का लक्ष्य

भारत सरकार 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। सहकारी क्षेत्र इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित तरीकों से योगदान देगाः

आत्मनिर्भर भारतः सहकारी समितियां स्थानीय स्तर पर उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी।

रोजगार सृजनः सहकारी क्षेत्र के विस्तार से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

कृषि क्षेत्र में क्रांतिः कृषि सहकारी समितियों को डिजिटल तकनीक से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाई जाएगी।

वित्तीय समावेशनः सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटीज ग्रामीण भारत को वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगी।

स्थानीय से वैश्विकः त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भारतीय सहकारी संगठनों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना सकें।

सहकारी संगठनों को पर्यावरण अनुकूल नीतियों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे सतत विकास को बल मिलेगा।

इस प्रकार, यह विश्वविद्यालय भारत में सहकारी आंदोलन को स्वर्णिम युग में प्रवेश कराने वाला एक ऐतिहासिक संस्थान साबित होगा, जो 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहकारी क्षेत्र की भूमिका को प्रभावी बनाएगा।■

-अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ(एनसीयूआई)

विशेष आलेख

अनिल कुमार तिवारी

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी: सहकारिता क्षेत्र की अनोखी पहल

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की एक और नई पहल के अंतर्गत त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, 2025 को सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश करने एवं संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के उपरांत आजादी के 78 वर्षों में पहली बार सहकारिता के सुदृढीकरण एवं बहुआयामी विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। उल्लेखनीय है कि गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा) का स्वरूप विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय देश का अनोखा विश्वविद्यालय होगा जिसका लक्ष्य सहकारिता में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, अनुसंधान एवं सलाहकार सेवाएं प्रदान कर सहकारिता क्षेत्र की गतिविधियों को प्रगतिशील एवं नवाचार में अग्रणी बनाना होगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना *'सहकार से समृद्धि'* को पूर्णरूपेण अमलीजामा पहनाने की दिशा में यह एक मजबूत कदम है। सहकारिता क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ा सुधार है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में आगामी वर्षों में सहकारी गतिविधियों के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अधिकतम योगदान के लक्ष्य को हासिल करने की उपलब्धि हासिल होगी।

देश के सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को देश का पहला सहकारिता मंत्री बनाया। यूनिवर्सिटी बनाने की सोच श्री अमित शाह के दिमाग की ही उपज है। दरअसल, प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आबादी को समृद्ध बनाया जा सकता है। खासतौर पर तब यह और महत्वपूर्ण है जब कृषि क्षेत्र में काम कर रही ज्यादातर आबादी किसी न किसी रूप में सहकारिता से जुड़ी है। देश में इस समय 8 लाख से ज्यादा सहकारी संस्थाएं हैं और इनके 30 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। देश के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की सोच थी कि जब देश में सहकारिता का इतना बड़ा स्वरूप है, तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी होना चाहिए और इसके माध्यम से कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किए जाने चाहिए ताकि भविष्य में सहकारी क्षेत्र की कुशल पेशेवरों की मांग पूरी की जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए ही देश में सहकारी आंदोलन की नींव रखने वाले त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया गया।

विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के गठन का उद्देश्य भारतीय सहकारी क्षेत्र में ज्ञान और अनुसंधान के साथ पेशेवर शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना है जिससे सहकारी समितियों के प्रबंधन में सुधार होगा। यह विश्वविद्यालय सहकारी समितियों के लिए एक नवाचारी और लचीला शैक्षिक ढांचा प्रदान करेगा एवं भारत के उत्कृष्ट संस्थानों, जैसे आईआईटी, आईआईएम आदि के साथ साझेदारी तथा समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से शैक्षणिक कौशल को सुनिश्चित करेगा। यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करेगा और सहकारी शासन एवं नवाचार के क्षेत्र में भारत की स्थिति को सशक्त बनाएगा।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना की अवधारणा हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है जिसमें विश्वविद्यालय हब (मुख्य केंद्र) तथा उसके दिशा-निर्देशन एवं मार्गदर्शन में संचालित होने वाले विविध संस्थान पूरे देश में स्पोक (द्वितीयक बिंदु) के रूप मे काम करेंगे जो अपने आप में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित एवं विकसित होंगे। हब एवं स्पोक मॉडल पर आधारित देश में फैले संस्थानों द्वारा ग्रामीण साख, दुग्ध, मत्स्य, सहकारी अंकेक्षण एवं अन्य पाठ्यक्रमों में योग्यता पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षण सहकारिता का सफल स्वरूप स्थापित किया जाएगा। इन पाठ्यक्रमों के स्वरूप में मूल्य संवर्द्धन करते हुए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी सहकारी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम तथा उद्योग विशेषज्ञों की भागीदारी से प्रभावी शिक्षा को क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना से लाभ

यह विश्वविद्यालय प्रशिक्षित मानव संसाधन की आपूर्ति करेगा एवं नई पहलों का क्रियान्वयन करेगा।

यह देशभर में फैले 284 विभिन सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों के संचालन को एक साथ लाने में सफल होगा।

यह सभी प्रशिक्षण संस्थानों के वार्षिक क्षमता निर्माण में वृद्धि करेगा।

यह विश्वविद्यालय सहकारिता क्षेत्र में दीर्घावधि पाठयक्रमों में वृद्धि करेगा।

विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थागत समेकित पद्धति के द्वारा सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण का समुचित स्वरूप विकसित किया जाए।■

लेखक सहकारी प्रबंधन संस्थान, देहरादून के निदेशक हैं।

सिक्किम के गंगटोक में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में एनसीयूआई के अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी ने सहकारी समितियों के प्रति एनसीयूआई की निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की और पूरे देश में सहकारिता की पहुंच बढ़ाने में संगठन के सहयोग पर जोर दिया।

एनसीयूआई द्वारा सहकारिता के संवर्धन और विकास पर सिक्किम स्टेट कॉपरेटिव यूनियन मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने सहकारिता क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रथम तीन समितियों को 15 अगस्त को क्रमशः 10 लाख, सात लाख और पांच लाख के प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।

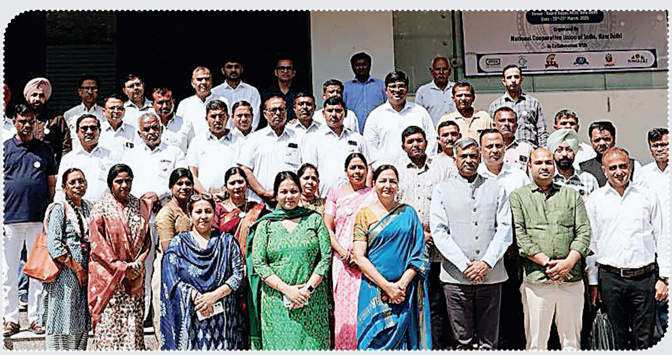

राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र ने जैविक और टिकाऊ कृषि के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एनसीओएल के प्रबंध निदेशक विपुल मित्तल और एनसीयूआई की उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह के साथ सात राज्यों से आए 35 प्रतिभागियों ने भागीदारी की।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में 'सहकारिताः सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी' विषय पर एनसीयूआई के जनसंपर्क एवं प्रकाशन प्रभाग ने प्रथम सहकारी युवा शोध सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें एनसीयूआई के मुख्य कार्यकारी डॉ. सुधीर महाजन, इफको के महाप्रबंधक श्री संतोष शुक्ल आदि गणमान्य व्यक्तियों ने भागीदारी की।

एनसीयूआई ने सहकारी समितियों और ग्रामीण वित्त पोषण संस्थाओं की महिला बोर्ड सदस्यों को शासन, नेतृत्व और निर्णय लेने में आवश्यक कौशल से सशक्त करने के लिए सीआईसीटीएबी और गुजरात राज्य सहकारी संघ के सहयोग से श्री डी.जी. पटेल सहकारी प्रबंधन केंद्र, सूरत में एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एनसीयूआई की उप मुख्य कार्यकारी श्रीमती सावित्री सिंह ने भी भागीदारी की।

एनसीयूआई के कॉप कनेक्ट डिवीजन ने सिक्किम के गंगटोक के रानीपूल में सीएईपीएचटी के ऑडिटोरियम में सहकारिता (सहकारी ओलंपियाड) पर राज्य स्तरीय युवा कार्यशाला की, जिसमें विभिन्न कॉलेजों के 90 से अधिक छात्र और संकाय सदस्यों के साथ आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ जगन्नाथ पटनायक सहित कई प्रोफेसर और एनसीयूआई व एसआईसीयूएन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भागीदारी की।

विकसित भारत के लिए भारत की कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण हो रहा है। हम कृषि क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं बनाने के साथ ही पैक्स जैसी सहकारी संस्थाओं को नई भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। पैक्स की उपयोगिता व उनके आय के साधन भी बढ़ रहे हैं। सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गांवों में सैकड़ों सरकारी सुविधाएं भी दे रही हैं। कंप्यूटर के जरिए ये समितियां टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया से जुड़े अवसरों को और बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाएंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। - श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

एनसीयूआई हाट, एनसीयूआई और कम प्रचलित सहकारी संस्थाओं के बीच नये आयाम स्थापित कर रहा है, जो उत्पांदों की बिक्री और प्रदर्शनी के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। अब एनसीयूआई हाट अपने नवीन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी *'सहकार से समृद्धि'* को साकार करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण कर रहा है।

CEAS-LMS Portal

कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (**CEAS-LMS**) अपने तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सहकारी सदस्यों को सहकारिता से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देता है। यह तीन चरण में काम करता है:

1. **LMS:** लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रत्येक चरण की सहकार शिक्षा दी जाती है।
2. **QMS:** क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मंच है जहां उपयोगकर्ता सहकारिता से जुड़े अपने मुद्दे रख सकते हैं, जिससे उन्हें तुरंत गुणवत्ता परक सलाह मिल सके।
3. **CRC:** कोऑपरेटिव रिर्सोस सेंटर सभी हितधारकों का प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से सहकारिता से जुड़े सभी सदस्य जानकारियों का आदान प्रदान कर सके।

https://ncuicoop.education/

नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के लिए संजय कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित और एनसीयूआई प्रिंटिंग प्रेस, बी-81, सेक्टर-80, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में मुद्रित। संपादक: संजय कुमार वर्मा

Postal Registration No DL-SW-01/4214/2023-2024
Published on 15.04.2024 Applied for Registration/ Exempted

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ